Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

जनवरी 2024 (संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- पहला 'ऑल-गर्ल्स सैनिक स्कूल' 3
- पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र' को परिभाषित करने हेतु परीक्षण आवश्यक: इलाहाबाद उच्च न्यायालय 3
- उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास 3
- तुलसीदास का जन्मस्थान 4
- आपदा पूर्व चेतावनी हेतु राहत वाणी केंद्र 4
- उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे 5
- अयोध्या में आध्यात्मिक पर्यटन का उदय 6
- उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा हब 6
- नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता-पिता के लिये जुर्माना 7
- उत्तर प्रदेश की 'अर्द्धचालक/सेमीकंडक्टर' नीति 7
- मुरादाबाद का पीतल बर्तन उद्योग 8
- MSME के लिये उत्तर प्रदेश शीर्ष तीन राज्यों में शामिल 9
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 10
- उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क 10
- उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रवेश करेगा 11
- स्वच्छ वायु लक्ष्य में विविध प्रगति 12
- उत्तर प्रदेश में 5 और हवाई अड्डे बनेंगे 12
- उत्तर प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि 12
- दिव्य अयोध्या' ऐप 13
- लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में यूपी अग्रणी 14
- उत्तर प्रदेश: सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों के लिये अनुकूल 15
- अयोध्या के लिये हेलीकाप्टर सेवा 16
- यूपी सरकार ने YEIDA, UPSIDA, UPEIDA के विस्तार के लिये 2,940 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी 16
- अभ्यास-अयुत्थाया और इंडो-थाई कॉर्पेट 17
- अयोध्या राम मंदिर 17
- उत्तर प्रदेश को अपनी आतिथ्य संस्कृति से परिचित कराने का अवसर 18
- राम मंदिर प्रतिष्ठा: राज्यों ने अवकाश घोषित किया 19
- रैपिड रेल कॉरिडोर के लिये 16,000 करोड़ रुपए की मंज़ूरी 19
- अयोध्या में BHISHM क्यूब 20
- कानपुर में GSVM मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 20
- उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2024 21
- खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर 22

नोट :

उत्तर प्रदेश

पहला 'ऑल-गर्ल्स सैनिक स्कूल'

चर्चा में क्यों ?

1 जनवरी, 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा के वृन्दावन में 'संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल' का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

- यह पहला पूर्णत: लड़कियों वाला सैनिक स्कूल (ऑल-गर्ल्स सैनिक स्कूल) है, जिसमें लगभग 870 छात्र हैं।
- यह सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में गैर-सरकारी संगठनों (NGO)/निजी/राज्य सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी मोड में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल के तहत बनाया गया है।
  - इनमें से 42 स्कूल पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं।
- इसे सशस्त्र बलों में शामिल होने की इच्छा रखने वाली लड़कियों के लिये आशा की किरण के रूप में वर्णित किया गया है।
  - वर्ष 2019 में, मिज़ोरम में सैनिक स्कूल छिंगछिप में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद राजनाथ सिंह ने चरणबद्ध तरीके से सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश को मंज़ूरी दी थी।
- 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित बेहतर कैरियर के अवसर प्रदान करना है।

पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र' को परिभाषित करने हेतु परीक्षण आवश्यक: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों ?

ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया रुख से पता चलता है कि उपासना स्थल अधिनियम, 1991 "किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र" को स्पष्ट नहीं करता है और प्रत्येक मामले में इसे केवल मौखिक तथा लिखित दोनों साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है।

मुख्य बिंदु:

- पूजा स्थल अधिनियम, 1991 धार्मिक स्थलों को किसी अलग धर्म या संप्रदाय के पूजा स्थलों में बदलने पर रोक लगाता है।
  - यह किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक पहचान को संरक्षित करने का भी आदेश देता है जैसा कि 15 अगस्त, 1947 को था।
- ज्ञानवापी मामला वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व और धार्मिक पहचान से संबंधित एक कानूनी लड़ाई है, जिसमें एक मस्जिद तथा एक मंदिर दोनों हैं।
- हिंदूवादी का तर्क है कि मस्जिद स्थल सहित पूरा क्षेत्र मूल रूप से स्वयंभू भगवान आदि विश्वेश्वर को समर्पित एक मंदिर था।
- उनका दावा है कि ज्ञानवापी भूखंड पर स्थित इस मंदिर को वर्ष 1669 में सम्राट औरंगज़ेब ने ध्वस्त कर दिया था।
- न तो सरकार और न ही सर्वोच्च न्यायालय ने आज तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट रुख अपनाया है।

उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास

चर्चा में क्यों ?

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में राज्य वर्ष 2017 में 14वें स्थान से बढ़कर वर्ष 2018 में देश में दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। यह उत्तर प्रदेश को देश में एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- राज्य सरकार ने एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है और उस दिशा में गंभीर प्रयास तब देखे गए जब फरवरी 2023 में यू. पी. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) आयोजित किया गया, जिसमें कुल 38 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
- ग्रेटर नोएडा में MotoGP का होना पर्यटन और परिणामस्वरूप, राज्य निवेश को बढ़ाने का एक शानदार तरीका था।
- ग्रेटर नोएडा में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्सव में सूचना प्रौद्योगिकी और इसकी सक्षम सेवाओं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों, निर्माताओं तथा निर्यातकों के लिये एक वैश्विक मंच प्रदान किया गया।
- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सुनिश्चित करने के लिये लागू की गई 25 क्षेत्रीय नीतियों के अलावा एक आकर्षक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नीति को 80 प्रतिशत तक अग्रिम भूमि सब्सिडी, 35 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी और निवल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहनों की पेशकश की गई थी।
  - जापानी कंपनी फूजी सिल्वरटेक कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड इस नीति के तहत सब्सिडी पाने वाली पहली कंपनी बन गई। सब्सिडी देने की पूरी प्रक्रिया तीन दिन के रिकॉर्ड समय में पूरी की गई है।
- आवश्यक लाइसेंस और प्रमाणपत्र एकल खिड़की निकासी प्रणाली, निवेश मित्र द्वारा प्रदान किये जाते हैं। इसके 8.8 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्त्ता हैं, जो 37 से अधिक विभागों में 454 से अधिक लाइसेंस से संबंधित सेवाएँ प्रदान करते हैं।
  - पोर्टल ने पिछले चार वर्षों में 97% की उल्लेखनीय सफलता दर के साथ NOC/लाइसेंस के लिये 13 लाख से अधिक आवेदनों पर कार्रवाई की है।
  - इसकी शिकायत निवारण दर 93% है।
- निवेश सारथी एक निवेशक प्रबंधन प्रणाली है जो राज्य में निवेशकों और उद्यमियों को ऑनलाइन प्रोत्साहन प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

तुलसीदास का जन्मस्थान

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट ज़िले के राजापुर गाँव को विकसित करने का निर्णय लिया है।

- यह संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्मस्थान है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना की थी।

मुख्य बिंदु:

- उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने रामचरितमानस के महत्त्व के साथ-साथ इसके लेखक पर भी ज़ोर दिया, जिनकी जन्मस्थली पर बड़ी संख्या में लोग पूजा करने आते हैं।
  - तुलसी रामायण का रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामायण का पुनर्कथन है।
- रामचरितमानस की डिजिटल उपलब्धता को सक्षम करने के लिये आवास और विभिन्न अन्य प्रावधानों सहित पर्यटन सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।
  - 21 करोड़ की लागत से राजापुर गाँव में तुलसी स्मारक के पास करीब ढाई एकड़ क्षेत्र का सौंदर्यीकरण होगा।
- औषधीय पौधों वाला पार्क, छात्रावास, डिजिटल लाइब्रेरी और इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा।
- वर्तमान समय में घरेलू पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष पर है। प्रदेश में पर्यटक सुविधाओं का लगातार विकास किया जा रहा है।

आपदा पूर्व चेतावनी हेतु राहत वाणी केंद्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्य में बहु-खतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत एक आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र 'राहत वाणी केंद्र' (RVC) का उद्घाटन किया।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- RVC's का कार्य आपदा पूर्व चेतावनियाँ तथा पूर्वानुमान की जानकारी उपलब्ध करना तथा समय पर राहत संबंधी वस्तुओं को पहुँचाना ताकि कर्मचारियों को मुआवज़े को सुव्यवस्थित किया जा सके।
- RVC's की स्थापना छह कर्मियों की एक टीम के साथ लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में की जाएगी।
- यह एक एकीकृत आपदा जोखिम प्रबंधन स्टैक और एक कुशल तकनीकी वातावरण विकसित करने के लिये भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), लखनऊ, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे; इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग; भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण; और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ समन्वय करेगा।
- RVC's के पीछे का उद्देश्य आम जनता को संभावित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में उनके प्रभाव से 30 मिनट से एक घंटे पहले सचेत करना है। सूचना समुदाय स्तर पर एसएमएस अलर्ट, मोबाइल नोटिफिकेशन और अन्य माध्यमों से प्रसारित की जाएगी।
- वर्तमान में IMD के 68 स्वचालित मौसम स्टेशन (AWSs) और 132 स्वचालित वर्षा गेज (AWSs) स्टेशन राज्य में मौसम संबंधी सुचना प्रदान करते हैं।
- पूर्व चेतावनी प्रणाली को और मज़बूत करने के लिये, राज्य सरकार और IMD पाँच डॉप्लर रडार (long-range weather forecasting and surveillance), 450 AWSs और 2000 ARG स्टेशन स्थापित कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे

चर्चा में क्यों ?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) को 'गंगा एक्सप्रेसवे' के निर्माण में तेज़ी लाने का निर्देश दिया है, जिसे वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

- लंबाई के आधार पर भारत के शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के चार एक्सप्रेस-वे हैं। गंगा एक्सप्रेस-वे के संचालन के साथ शीर्ष 10 में यूपी के पाँच एक्सप्रेस-वे शामिल हो जाएंगे।

मुख्य बिंदु:

- यह गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढाँचे और विकास को नया आकार देने हेतु महत्त्वपूर्ण तथा वर्ष 2025 में महाकुंभ से पहले ही इस बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेस-वे को शुरू करने की रणनीतिक पहल है।
- गंगा एक्सप्रेस-वे मुंबई-नागपुर एक्सप्रेस-वे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे है।
  - यह 594 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई वाला एक महत्त्वाकांक्षी पहल है।
  - यह यात्रा दक्षता को फिर से परिभाषित करने और अपने विशाल गलियारे में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये तैयार है।
- गंगा एक्सप्रेस-वे की विशेषताएँ:
  - राज्य को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने वाला यह एक्सप्रेस-वे 12 ज़िलों के 518 गाँवों से होकर गुज़रेगा, जिससे मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
  - इसे शुरुआत में छह लेन के लिये डिज़ाइन किया गया है, जिसे आठ लेन तक बढ़ाया जा सकता है और इसकी अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है।
  - एक अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता में गंगा और रामगंगा नदियों पर बने दो लंबे पुल शामिल हैं, जो बड़े विमानों को भी उतरने की अनुमति देते हैं। शाहजहाँपुर में जलालाबाद तहसील के पास 3.50 किलोमीटर की हवाई पट्टी परियोजना की बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाती है।
  - सार्वजनिक सुविधा बढ़ाने के लिये एक्सप्रेस-वे के किनारे नौ सार्वजनिक सुविधा परिसरों की योजना बनाई गई है, जिसमें मेरठ और प्रयागराज में मुख्य टोल प्लाज़ा तथा 15 स्थानों पर रैंप टोल प्लाज़ा प्रस्तावित हैं।
- गंगा एक्सप्रेस-वे केवल एक परिवहन लिंक नहीं है, बल्कि अपने एडवेंचर लैंडस्केप को आधुनिक बनाने के लिये उत्तर प्रदेश के विस्तार का एक प्रमाण है।

नोट :

अयोध्या में आध्यात्मिक पर्यटन का उदय

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और विकास कार्य पूरा होने के बाद से शहर में पर्यटन दस गुना बढ़ने की संभावना है।

- राम मंदिर के उद्घाटन में 7,000 लोगों के आने की उम्मीद है। मंदिर खुलने के बाद, अयोध्या विकास प्राधिकरण के अनुसार अगले महीने (फरवरी) तक प्रत्येक दिन 3,00,000-5,00,000 आगंतुकों के आने की संभावना है।

मुख्य बिंदु:

- भारत के अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की बहुप्रतीक्षित 'प्राण प्रतिष्ठा' (Consecration Ceremony) 22 जनवरी, 2024 को होगी।
- मंदिर के उद्घाटन की तैयारी में शहर में बड़े सुधार हुए हैं:
  - अयोध्या के आध्यात्मिक पर्यटन में वृद्धि: राम मंदिर के उद्घाटन से पहले, अयोध्या में होटल की दरें कथित तौर पर बढ़ गईं है जिनमें से बहुत-सी पहले ही बुक हो चुकी हैं।
  - टेम्पल टाउन के लिये ट्रेनें: अमृत भारत ट्रेनें एक नई तरह की सुपरफास्ट ट्रेन हैं जिसमें आधुनिक तकनीक, तेज़ गति और आरामदायक सफर जैसी कई सुविधाएँ मिल जाती हैं।
    - वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख मंदिरों - राम जन्मभूमि और गोरखनाथ को जोड़ेगी।
  - नया अयोध्या हवाई अड्डा: पवित्र कार्यक्रम के बाद प्रत्येक दिन राम मंदिर के दर्शन के लिये आने वाले लाखों लोगों को समायोजित करने हेतु एयरलाइंस का दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से सेवा प्रदान करने का इरादा है।
- राम मंदिर के निर्माण से पहले ही अयोध्या की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ज़िले में आने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार के नए अवसर पैदा करती है।
  - मंदिर के पास कई नए व्यवसाय विकसित हुए हैं, जो पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के देशी हस्तशिल्प प्रदान करते हैं।

उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा हब

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA) के अनुसार, उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय वाली 125 परियोजनाएँ हैं।

- ये परियोजनाएँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सौर और वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से राज्य की 40% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।

मुख्य बिंदु:

- पहले चरण में बुंदेलखण्ड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में 35,000 करोड़ रुपए की चार बड़ी सौर परियोजनाएँ स्थापित की जाएंगी।
- वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (GIS) में राज्य सरकार को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।
- 'अक्षय ऊर्जा' योजना के तहत सौर ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का कुल निवेश में महत्त्वपूर्ण हिस्सा था।
- राज्य वर्तमान में लगभग 2152 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसमें से 372 मेगावाट तक स्वतंत्र रूप से पहुँच है।
  - बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में सौर संयंत्र लगे हैं, जो राज्य में उत्पादित कुल सौर ऊर्जा का लगभग 60% है।
- राज्य का सौर ऊर्जा उत्पादन, जो वर्ष 2017 में 279 मेगावाट के करीब था, पिछले छह वर्षों में कई गुना वृद्धि देखी गई है, जिसमें राज्य सरकार की नई सौर नीति के तहत दिये गए प्रोत्साहन, छूट, रियायतें और पदोन्नति शामिल हैं।

नोट :

- मौजूदा निवेश पाइपलाइन के तहत, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ग्रीनको ग्रुप द्वारा 17,000 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय पर 3660 मेगावाट विद्युत् उत्पन्न करने वाली 'ऑफ-स्ट्रीम क्लोज़ लूप पंप स्टोरेज' परियोजना की स्थापना की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बखिरा पक्षी अभयारण्य में 50 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है।
- सोलर सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत NTPC द्वारा अयोध्या में 165 एकड़ भूमि पर 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। परियोजना का एक हिस्सा पहले ही शुरू हो चुका है और शेष मार्च 2024 तक चालू होने की उम्मीद है।

नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता-पिता के लिये जुर्माना

चर्चा में क्यों ?

नाबालिगों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास में, उत्तर प्रदेश सरकार ने नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता-पिता या वाहन मालिकों पर तीन वर्ष की कैद और 25,000 रुपए जुर्माने के प्रावधान को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।

मुख्य बिंदु:

- परिवहन विभाग के सहयोग से सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न माध्यमों से सड़क सुरक्षा पर ज़ोर देते हुए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।
- मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 199 (ए) के तहत, यह रेखांकित किया गया है कि किशोरों द्वारा किये गए मोटर वाहन-संबंधी अपराधों में, केवल उनके अभिभावक या वाहन मालिक को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
  - निर्धारित सज़ा में तीन वर्ष की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना शामिल है।
- लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और लोहिया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों के अनुसार सड़क दुर्घटना में होने वाली 40% मौतों में नाबालिग शामिल हैं।
- अधिकारियों ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा ड्राइविंग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया और सभी शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाने की बात की।

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019

- संशोधन यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड लगाने, लाइसेंसिंग और इसके प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा देश में सड़क सुरक्षा की खराब स्थिति को दूर करने का प्रयास करता है।
- यह एक मोटर वाहन दुर्घटना निधि का प्रावधान करता है, जो भारत में सभी सड़क उपयोगकर्त्ताओं को कुछ दुर्घटनाओं के लिये अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करता है।
- यह केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का भी प्रावधान करता है।

उत्तर प्रदेश की 'अर्द्धचालक/सेमीकंडक्टर' नीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राज्य की 'सेमीकंडक्टर' नीति तैयार करने का आदेश दिया।

- यह निर्णय तेज़ी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी संचालित वैश्विक अर्थव्यवस्था में अर्द्धचालकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

मुख्य बिंदु:

- वित्तीय वर्ष 2022 में वैश्विक अर्द्धचालक/सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र से 950 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
  - सेमीकंडक्टर चिप सेक्टर ने पिछले दो वर्षों में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश की घोषणा की है।

नोट :

- केंद्र सरकार द्वारा अर्द्धचालक विनिर्माण सेवाओं, जैसे– सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब और कंपाउंड सेमीकंडक्टर के लिये प्रोत्साहन दी जा रही है।
  - वर्ष 2021 में, भारत ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) की घोषणा की।
  - सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र के लिये, निर्माण इकाइयाँ, मिक्स्ड सेमीकंडक्टर, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर, असेंबली एंड टेस्ट यूनिट, पैकेजिंग यूनिट्स एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं।
- वैश्विक अर्द्धचालक निवेशकों को आकर्षित करने के लिये उत्तर प्रदेश की नीति के तहत वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन के वितरण का प्रावधान किया जाना चाहिये।
- सेमीकंडक्टर/अर्द्धचालक
- अर्द्धचालक, एक चालक और कुचालक के बीच विद्युत चालकता में मध्यवर्ती क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का एक वर्ग होता है।
- अर्द्धचालकों का उपयोग डायोड, ट्रांजिस्टर और एकीकृत सर्किट सहित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है।
  - इस तरह के उपकरणों को उनकी कॉम्पैक्टनेस, विश्वसनीयता, विद्युत दक्षता और कम लागत के कारण व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है।

मुरादाबाद का पीतल बर्तन उद्योग

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से धार्मिक मूर्तियों, विशेष रूप से भगवान राम की मूर्तियों की मांग में वृद्धि के रूप में हुई है, जिसके परिणामस्वरूप मुरादाबाद के पीतल के बर्तन उद्योग के पुनरुत्थान को प्रोत्साहन मिला है।

मुख्य बिंदु:

- मुरादाबाद की स्थापना वर्ष 1600 में मुगल सम्राट शाहजहाँ के बेटे मुराद ने की थी, जिसके परिणामस्वरूप शहर को मुरादाबाद के नाम से जाना जाने लगा।
- यह पीतल के कार्य के लिये प्रसिद्ध है, जिसने पूरे विश्व में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
  - पीतल के बर्तन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, मध्य पूर्व और एशिया जैसे देशों में निर्यात किये जाते हैं। इसलिये मुरादाबाद को "ब्रास सिटी" या पीतल नगरी भी कहा जाता है।
  - पीतल, ताँबे और जस्ता की एक मिश्र धातु है, जो अपनी उल्लेखनीय कठोरता तथा व्यावहारिकता के कारण ऐतिहासिक व स्थायी महत्त्व रखती है।
- 1980 के दशक में, पीतल, लोहा और एल्यूमीनियम जैसे विभिन्न धातु के बर्तनों की शुरुआत के साथ उद्योग में विविधता आई। इस विस्तार से मुरादाबाद के कला उद्योग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लैकरिंग और पाउडर कोटिंग जैसी नई तकनीकें विकसित हुई।
- मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट (वर्ड मार्क) को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त है।
- 'एक ज़िला एक उत्पाद कार्यक्रम' (ODOP) के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों तथा कला को प्रोत्साहित करती है।

उत्तर प्रदेश के एक ज़िला एक उत्पाद कार्यक्रम (ODOP) के मुख्य उद्देश्य

- स्थानीय कला/कौशल का संरक्षण एवं विकास तथा रचनात्मकता को बढ़ावा देना।
- आय और स्थानीय रोज़गार में वृद्धि (परिणामस्वरूप रोज़गार के लिये प्रवासन में कमी)।
- उत्पाद की गुणवत्ता और कौशल विकास में सुधार।
- उत्पादों को कलात्मक तरीके (पैकेजिंग, ब्रांडिंग के माध्यम से) से बदलना।

नोट :

- उत्पादन को पर्यटन से जोड़ना (लाइव डेमो और बिक्री आउटलेट - उपहार तथा स्मारिका)।
- आर्थिक मतभेद और क्षेत्रीय असंतुलन के मुद्दों को हल करना।
- राज्य स्तर पर सफल कार्यान्वयन के बाद ODOP की अवधारणा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना।

उत्तर प्रदेश में ODOP उत्पादों की सूची

क्रमांक	ज़िला	उत्पाद
1.	आगरा	चमड़ा उत्पाद एवं स्टोन/मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प उत्पाद
2.	अमरोहा	वाद्य यंत्र (ढोलक) एवं रेडीमेड गारमेंट्स
3.	बागपत	होम फर्नीशिंग
4.	बरेली	ज़री-ज़रदोज़ी एवं बाँस के उत्पाद/सुनारी उद्योग
5.	गोरखपुर	टेराकोटा एवं रेडीमेड गार्मेंट्स
6.	लखनऊ	चिकनकारी एवं ज़री ज़रदोज़ी
7.	महोबा	गौरा पत्थर
8.	मिर्ज़ापुर	कालीन एवं मेटल उद्योग
9.	सिद्धार्थनगर	काला नमक चावल
10.	वाराणसी	बनारसी रेशम साड़ी

MSME के लिये उत्तर प्रदेश शीर्ष तीन राज्यों में शामिल

चर्चा में क्यों ?

रियल्टी कंसल्टिंग फर्म CBRE साउथ एशिया और रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन CREDAI की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल पंजीकृत MSME में 9% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता के रूप में शीर्ष तीन राज्यों में उभरा है।

- क्षेत्र-वार, रिपोर्ट में बताया गया है कि निर्माण क्षेत्र, सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान देता है, जो भारतीय MSME के लिये एक रणनीतिक अवसर है।

मुख्य बिंदु:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, मंत्रालय के तहत 2.21 करोड़ MSME पंजीकृत हैं (उद्यम असिस्ट पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण को छोड़कर)।
  - उत्तर प्रदेश के कई शहर MSME क्लस्टर के रूप में उभरे हैं, जिनमें आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और गाज़ियाबाद उद्यम योजना के लिये नामांकन में अग्रणी हैं।
- जिनमें से 17.2% हिस्सेदारी के साथ 38.09 लाख महाराष्ट्र से थे, इसके बाद तमिलनाडु से 10% हिस्सेदारी के साथ 22.32 लाख और 9.4% हिस्सेदारी के साथ 20.95 लाख उत्तर प्रदेश से थे।
- 16 लाख के साथ राजस्थान और 15.96 लाख MSME के साथ गुजरात देश में पंजीकृत इकाइयों के लिये अन्य शीर्ष स्थान थे।
- सरकार, उद्योग हितधारकों और वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोगात्मक प्रयास एक मज़बूत समर्थन प्रणाली बनाने में सहायता कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि MSME को उभरते आर्थिक परिदृश्य को नेविगेट करने के लिये आवश्यक संसाधन तथा मार्गदर्शन प्राप्त हो।

उद्यम पोर्टल

- यह MSME को पंजीकृत करने के लिये एक ऑनलाइन प्रणाली है, जिसे 1 जुलाई, 2020 को केंद्रीय MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
- यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) के डेटाबेस से जुड़ा हुआ है।

नोट :

- GSTN एक अद्वितीय और जटिल IT उद्यम है जो करदाताओं, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के बीच संचार एवं बातचीत का एक चैनल स्थापित करता है।
- यह पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसके लिये किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होती है और यह MSME के लिये ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की दिशा में एक कदम है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023

चर्चा में क्यों ?

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिये प्रयागराज और वाराणसी को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, झाँसी और फिरोज़ाबाद सहित आठ शहरों ने 3-स्टार रेटिंग अर्जित की है, जबकि नोएडा ने पाँच-स्टार रेटिंग अर्जित की है।
- राज्य के लगभग 648 शहरों ने खुले में शौच मुक्त (ODF) का दर्जा हासिल कर लिया है। वहीं 65 शहरों ने 'कचरा मुक्त शहर' का दर्जा हासिल किया।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणामों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के 129 शहरों ने ओडीएफ++ का दर्जा हासिल कर लिया है, जो खुले में शौच-मुक्त मानकों और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के पालन को दर्शाता है।
- राज्य के 435 शहरों ने ओडीएफ+ का दर्जा प्राप्त किया है, जो राज्य में स्वच्छता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- उत्तर प्रदेश के कई शहर अब 7-स्टार रेटिंग की ओर बढ़ रहे हैं।
- सरकार द्वारा अधिक शहरों को 5-स्टार और 3-स्टार रेटिंग प्राप्त करवाने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023

- बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए शहरों को शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रतिस्पर्धी ढाँचे के रूप में वर्ष 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी।
- पिछले कुछ वर्षों में, स्वच्छ सर्वेक्षण विश्व में सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में उभरा है।

उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ललितपुर, बुंदेलखंड में पाँच गाँवों में 1,472 एकड़ में एक फार्मा पार्क स्थापित कर रही है।

- फार्मा पार्क की स्थापना और संबंधित परियोजनाओं में तेज़ी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।

मुख्य बिंदु:

- योजना दो चरणों में सामने आएगी, जिसमें शुरुआती केंद्र 300 एकड़ भूमि को कवर करने वाले तत्काल विकास प्रयासों पर होगा।
  - सर्वेक्षण के लिये चिह्नित गाँवों में सैदपुर, गडोलीकला, लारगन, करौंदा और रामपुर शामिल हैं।
- सर्वेक्षण तकनीकों में तेल परीक्षण, समोच्च मानचित्रण और स्थलाकृतिक जाँच शामिल हैं।
  - आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग इन पहलों की योजना और कार्यान्वयन में सटीकता तथा दक्षता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

नोट :

- UPSIDA दिबियापुर में प्लास्टिक सिटी परियोजना के साथ-साथ उरई में साइट-1 और साइट-2 पर विकास परियोजनाओं में तेज़ी लाने के लिये भी कदम उठा रहा है।
  - 274.4 एकड़ में फैला प्लास्टिक पार्क, औद्योगिक इकाइयों, आवासीय क्षेत्रों और बुनियादी ढाँचे को शामिल करता है।

उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रवेश करेगा

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार, उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। राज्य 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है।

मुख्य बिंदु:

- पिछले साढ़े छह वर्षों के योजनाबद्ध प्रयासों से वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी स्थिति में है।
- राज्य का कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो वर्ष 2021-22 में ₹16.45 लाख करोड़ था, अब वर्ष 2022-23 में बढ़कर ₹22.58 लाख करोड़ से अधिक हो गया है।
  - राष्ट्रीय आय में 9.2% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, जो देश के आर्थिक विकास के मुख्य चालक के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
  - वर्ष 2021-22 में वर्तमान और स्थिर कीमतों पर उत्तर प्रदेश की विकास दर क्रमश: 20.1% तथा 9.8% थी, जबकि देश की विकास दर 18.4% तथा 9.1% थी।
  - इसी प्रकार, वर्ष 2022-23 में, राज्य की विकास दर 9.8% के मुकाबले स्थिर कीमतों की राष्ट्रीय वृद्धि दर 7.2% दर्ज की गई, जबकि इस अवधि के दौरान राज्य की मौजूदा कीमतों की वृद्धि दर 14.3% दर्ज की गई।
- डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण जैसी पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने के साथ अर्थव्यवस्था के प्राथमिक खंड में सुधार के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है।
  - वर्ष 2021-22 में गन्ने की खेती का क्षेत्र और उत्पादन 26.8% बढ़ गया, जबकि बागवानी फसल उत्पादन में 31.9% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई।
  - उत्तर प्रदेश में दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से राज्य प्रायोजित योजनाओं के अनुकूल परिणाम मिल रहे हैं। हालाँकि, फसल विविधीकरण को और बढ़ाने तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता है।
- दुग्ध उत्पादन में प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, अंडा उत्पादन में प्रगति के मामले में यह 12.80% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करके तीसरे स्थान पर है।
- उत्तर प्रदेश ने होटल/रेस्तरां, परिवहन, संचार, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाओं, सार्वजनिक सेवाओं, रक्षा और अन्य सेवाओं में वृद्धि के साथ तृतीयक क्षेत्र में तेज़ी से विकास हासिल किया। पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं में अभूतपूर्व विकास हुआ है।
  - वर्ष 2023 में भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश को वर्ष 2022 में सबसे अधिक पर्यटक आगमन का गौरव प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, राज्य ने 31.8 करोड़ से अधिक पर्यटकों का स्वागत किया, जिसमें वाराणसी, मथुरा और अयोध्या प्रमुख केंद्र बनकर उभरे।
    - घरेलू पर्यटकों की सुविधा के अलावा, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये एक व्यापक कार्य योजना विकसित करना अनिवार्य है और इसके लिये संभावित देशों की पहचान करने तथा उचित नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है।
- योजना विभाग के प्रधान सचिव एवं वित्तीय परामर्श कंपनी डेलॉयट के प्रतिनिधियों ने राज्य के वर्तमान आर्थिक परिवेश के विषय में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने वर्तमान स्थिति और संभावित भविष्य के परिणामों, उद्योग की अपेक्षाओं तथा क्षेत्र-वार अन्य प्रासंगिक विवरणों के विषय में विस्तार से बताया।
- वर्ष 2027 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य तक पहुँचने के लिये यह ज़रूरी है कि सभी विभाग अपने प्रयासों को बढ़ाएँ। जिसके लिये बेहतर योजना और समन्वय की आवश्यकता है।

नोट :

स्वच्छ वायु लक्ष्य में विविध प्रगति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, क्लाइमेट ट्रेंड्स और रेस्पिरर लिविंग साइंस ने एक अध्ययन किया है, जिसमें बताया गया है कि अधिकांश शहर भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के स्वच्छ वायु लक्ष्य से बहुत दूर हैं।

मुख्य बिंदु

- पाँच वर्षों में लगातार PM 2.5 डेटा वाले 49 शहरों में से केवल 27 शहरों में PM 2.5 के स्तर में गिरावट देखी गई, जबकि केवल चार शहर NCAP लक्ष्यों के अनुसार लक्षित गिरावट को पूरा कर पाए या उससे आगे निकल गए।
  - वायु में PM 2.5 की मात्रा वायु गुणवत्ता का एक प्रमुख संकेतक है।
  - PM का अर्थ पार्टिकुलेट मैटर है और 2.5 का अर्थ पार्टिकुलेट मैटर के आकार से है।
- जबकि वाराणसी, आगरा और जोधपुर जैसे कुछ शहरों में PM2.5 के स्तर में उल्लेखनीय कमी देखी गई, दिल्ली सहित अन्य शहरों में मामूली गिरावट (केवल 5.9%) या यहाँ तक कि प्रदूषण भार में वृद्धि दर्ज की गई।
- वाराणसी में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक PM 2.5 के स्तर में 72% की औसत कमी और PM 10 के स्तर में 69% के साथ सबसे अधिक कमी देखी गई।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

- इसे जनवरी 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा लॉन्च किया गया था।
- समयबद्ध कमी लक्ष्य के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये एक राष्ट्रीय ढाँचा तैयार करने का यह देश में पहला प्रयास है।
- NCAP का लक्ष्य 131 शहरों में वर्ष 2026 तक औसत पार्टिकुलेट मैटर (PM) सांद्रता को 40% तक कम करना है। प्रारंभ में वर्ष 2024 तक 20-40% की कटौती का लक्ष्य रखा गया था, बाद में इस लक्ष्य को वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया।

उत्तर प्रदेश में 5 और हवाई अड्डे बनेंगे

चर्चा में क्यों ?

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में पाँच नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- राज्य में आजमगढ़, अलीगढ, मोरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में हवाई अड्डे बनेंगे जिससे राज्य में कुल हवाई अड्डों की संख्या 19 हो जाएगी।
- अयोध्या हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा और बड़े विमानों को उतरने तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की अनुमति देने के लिये रन-वे का विस्तार किया जाएगा।
  - इसका दूसरे चरण का विस्तार जल्द ही शुरू होगा और अधिक उड़ानें शहर को जोड़ेंगी।
  - अयोध्या में महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर, 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था।

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा तैयार यूपी के लिये स्टेट फोकस पेपर 2024-25 के अनुसार, वर्ष 2024-25 में यूपी के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह 5.73 ट्रिलियन रुपए तक पहुँचने का अनुमान है।

- कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) और सेवा क्षेत्र को सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिये राज्य को कृषि में 250%, MSME में 300% और सेवा क्षेत्र में 450% की वृद्धि दर की आवश्यकता होगी।
  - विकास के उत्प्रेरक के रूप में ऋण के महत्त्व को रेखांकित करते हुए, यूपी सरकार ने बैंकरों को राज्य के ऋण जमा (CD) अनुपात में सुधार करने के लिये प्रेरित किया है।
  - यूपी को एक अग्रणी निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिये राज्य का एक प्रतिनिधिमंडल स्विट्ज़रलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में भाग ले रहा है।
  - राज्य रोज़गार सृजन के लिये स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे रहा है। यूपी के एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) ने भारत स्टार्टअप एंड इनोवेशन सोसाइटी (BSIS) के साथ साझेदारी की है, जो एक धर्मार्थ समाज है जो उद्यमियों की अगली पीढ़ी के पोषण और मार्गदर्शन पर कार्य करता है।
- नाबार्ड, यूपी के मुख्य महाप्रबंधक ने 19.2% की अनुमानित विकास दर के साथ राज्य को भारत का "विकास इंजन" कहा है।
  - ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में राज्य वर्ष 2017 में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है।
- स्टेट फोकस पेपर सभी 75 ज़िलों के लिये ज़मीनी स्तर पर ऋण संभावनाओं को संकलित करता है।
  - पेपर के आधार पर, वर्ष 2024-25 के लिये वार्षिक क्रेडिट योजना को यूपी में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।
- राज्य, फसल की गुणवत्ता में सुधार करके कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कदम उठा रहा है।
  - भारत के कुल कदन्न/मिलेट्स उत्पादन में यूपी का योगदान 20% है, लेकिन निर्यात केवल 1% था।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF)

- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) एक स्विस गैर-लाभकारी संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में हुई थी।
- स्विस सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- WEF वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र तथा समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिये प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)

- नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिये शीर्ष बैंकिंग संस्थान है।
- इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में अवस्थित है।
- कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिये उत्तरदायी है।
- यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत की गई थी।

दिव्य अयोध्या' ऐप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप 'दिव्य अयोध्या' लॉन्च किया, जिसे अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिये नेविगेशनल अनुभव को बढ़ाने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

- 'दिव्य अयोध्या' ऐप प्रौद्योगिकी को सांस्कृतिक अनुभवों के साथ जोड़कर और ग्रामीण परिवेश में होमस्टे जैसे विकल्प प्रदान कर, पर्यटकों को पवित्र शहर से जुड़ने की सुविधा प्रदान करती है, जो सभी के लिये अधिक उपयोगी तथा समृद्ध अनुभव प्रदान करता है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- यह ऑल-इन-वन प्लेटफॉर्म यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाने और छिपे हुए रत्नों की खोज तथा अयोध्या के सांस्कृतिक वैभव का अनुभव करने तक सभी ज़रूरतों को पूरा करता है।
  - यह विस्तृत विवरण और समय सारिणी के साथ प्रमुख स्थलों, मंदिरों, मठों और ऐतिहासिक स्थलों की खोज में भी मदद करेगा।
  - ऐप ई-कारों और ई-बसों को बुक करने, उनके रूट की स्थिति को ट्रैक करने तथा सुविधाजनक बोर्डिंग एवं डीबोर्डिंग में भी मदद करेगा।
  - होमस्टे, होटल या यहाँ तक कि टेंट सिटी के लिये बुकिंग भी ऐप से संभव है, जो उपयोगकर्त्ताओं को स्थानीय रूप से प्रशिक्षित पर्यटक गाइडों से जोड़ता है।
  - इसके अतिरिक्त, ऐप सहज दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिये व्हीलचेयर और गोल्फ कार्ट भी बुक किये जा सकते हैं।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी सरकार ग्रामीण परिवेश में होमस्टे विकल्प प्रदान करने के लिये अयोध्या के बाहरी इलाके में स्थानों की पहचान कर रही है।
  - अयोध्या आने वाले परिवार खेत में रहने के अनुभव के लिये दौलतपुर गाँव में एक घर का एक हिस्सा किराये पर ले सकते हैं।
  - इन पहलों का उद्देश्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है बल्कि स्थायी पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देना भी है।
- राज्य सरकार अयोध्या में राम जन्मभूमि और मंदिरों जैसे प्रमुख स्थलों पर जाने वाले पर्यटकों तथा तीर्थयात्रियों हेतु सुविधाएँ बढ़ाने के लिये भी तैयार है। 'धर्म पथ' और 'राम पथ' पर इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत इन प्रयासों का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य आवश्यक सेवाएँ प्रदान करना है।

लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में यूपी अग्रणी

चर्चा में क्यों ?

नीति आयोग द्वारा जारी एक पेपर 'भारत में बहुआयामी गरीबी 2005-06' के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने पिछले नौ वर्षों में बहुआयामी गरीबी (MDP) से अधिकतम संख्या में लोगों को बाहर निकालने में राज्यों के बीच अपना नेतृत्व बनाए रखा है।

- संगठन ने बताया कि यूपी में 5.94 करोड़ लोग MDP से निकले हैं।

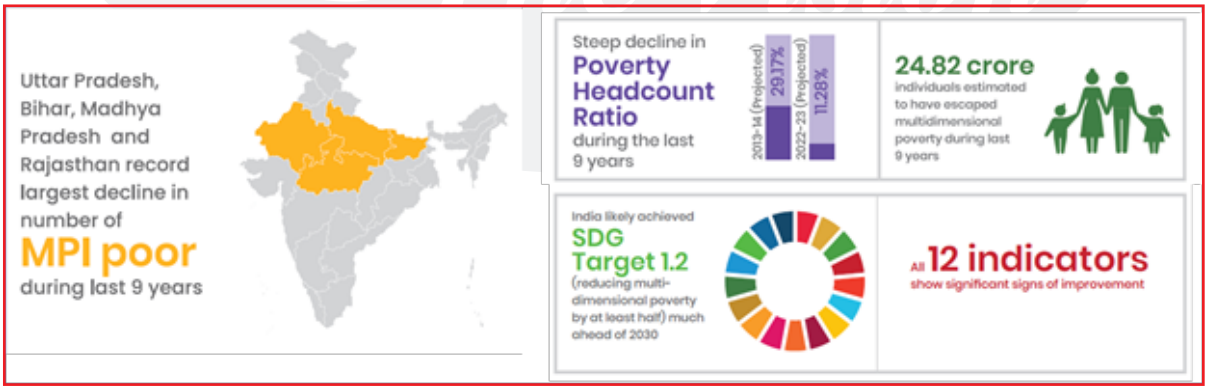

मुख्य बिंदु:

- पेपर में, यह बताया गया था कि वर्ष 2015-16 में 37.68% से यूपी में बहुआयामी गरीबों की संख्या वर्ष 2019-21 में घटकर 22.95% हो गई।
- नीति आयोग के पेपर में कहा गया है कि वर्ष 2022-23 में यह आँकड़ा घटकर 17.40% रह गया है।
  - नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी को मापने के लिये सतत् विकास लक्ष्यों से जुड़े 12 संकेतकों पर विचार किया।
- ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने भी पेपर में योगदान दिया।

नोट :

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में 11.28% हो गई और इस अवधि के दौरान 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए।

नीति आयोग

- योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें 'सहकारी संघवाद' की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना की परिकल्पना के लिये 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया गया था।
- इसके दो हब हैं:
  - टीम इंडिया हब- राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है।
  - ज्ञान और नवोन्मेष हब- नीति आयोग के थिंक-टैंक की भाँति कार्य करता है।

ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI)

- OPHI ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के अंतर्गत एक आर्थिक अनुसंधान और नीति केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी।
- इसका उद्देश्य लोगों के अनुभवों और मूल्यों पर आधारित बहुआयामी गरीबी को कम करने के लिये एक अधिक व्यवस्थित प्रणाली तथा आर्थिक ढाँचे का निर्माण करना एवं उसे आगे बढ़ना है।

उत्तर प्रदेश: सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों के लिये अनुकूल

चर्चा में क्यों ?

एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की प्रस्तावित सेमीकंडक्टर नीति 2024 पर आधारित प्रस्तुतीकरण की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये।

मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योगों में उन्नति के साथ-साथ उच्च दक्षता वाले उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और चिकित्सा संबंधित उपकरणों में के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम कंप्यूटिंग में नवाचार को भी बढ़ावा देता है।
- यह राज्य की आर्थिक वृद्धि और नवाचार में योगदान देगा तथा रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए पर्याप्त रोज़गार के अवसर भी उत्पन्न करेगा।
- युवाओं को सेमीकंडक्टर निर्माण में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री ने राज्य के दो IIT सहित तकनीकी संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रमों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा।
  - सेमीकंडक्टर उद्योगों में CM इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत युवाओं के लिये दो वर्ष के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- सेमीकंडक्टर चिप क्षेत्र ने पिछले दो वर्षों में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश करने की योजना की घोषणा की है।
  - सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिये, भारत सरकार ने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रोत्साहन परिव्यय प्रदान करने का निर्णय लिया है।
- सीएम का सुझाव है कि नीति में वैश्विक सेमीकंडक्टर निवेशकों को आकर्षित करने के लिये वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन के वितरण के प्रावधान शामिल होने चाहिये।
  - ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य होगा।
- नई नीति में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजी के अलावा अतिरिक्त पूंजी निवेश भी शामिल होना चाहिये।
  - भूमि की खरीद/पट्टे पर स्टाम्प शुल्क में छूट का भी प्रावधान होना चाहिये।
- नीति में विद्युत शुल्क में छूट, ड्यूल पावर ग्रिड नेटवर्क ट्रांसमिशन एवं व्हीलिंग शुल्क, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, पेटेंट, जल आपूर्ति, पावर बैंकिंग, अनुसंधान और विकास सहायता हेतु प्रावधान किये जाने चाहिये।

नोट :

अयोध्या के लिये हेलीकाप्टर सेवा

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा से अयोध्या के लिये हेलीकॉप्टर सेवाएँ देने का निर्णय किया है।

मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 जनवरी को लखनऊ से हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन करेंगे।
  - सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिये किराया भी निर्धारित कर दिया है और निकट भविष्य में इसे राज्य के अन्य ज़िलों में भी विस्तारित करने की योजना पर कार्य चल रहा है।
- राज्य सरकार भक्तों के लिये अयोध्या शहर और राम मंदिर का ऐरियल दर्शन भी शुरू कर रही है। इस पहल के लिये पर्यटन विभाग को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
  - हेलीकॉप्टर की सवारी सरयू नदी के किनारे टूरिज़्म गेस्ट हाउस के पास बने हेलीपैड से होगी।
  - भक्त राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और सरयू घाट सहित प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की हवाई यात्रा का आनंद लेंगे।
  - वाराणसी में नमो घाट से, लखनऊ में रमाबाई से, प्रयागराज में टूरिज़्म गेस्ट हाउस के पास हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सेवाएँ उपलब्ध हैं।
  - श्रद्धालु मथुरा के बरसाना में गोवर्धन परिक्रमा के पास हेलीपैड और आगरा में आगरा एक्सप्रेस-वे के पास हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सेवाओं का विकल्प चुन सकते हैं।
  - क्रमश: 456 कि.मी. और 440 कि.मी. तक फैले इन लंबे मार्गों को पूरा होने में 135 मिनट लगते हैं तथा इसके लिये प्रति श्रद्धालु किराया 35,399 रुपए तय किया गया है।

सरयू नदी

- सरयू एक नदी है जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है।
- इस नदी का प्राचीन महत्त्व है क्योंकि इसका उल्लेख वेदों और रामायण में मिलता है।
- यह नदी करनाली और महाकाली नदियों के संगम पर बनती है। यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है।
- भगवान राम के जन्मदिन का जश्न मनाने वाले त्योहार राम नवमी पर, हज़ारों लोग अयोध्या में सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं।

यूपी सरकार ने YEIDA, UPSIDA, UPEIDA के विस्तार के लिये 2,940 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निकायों, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA), यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) और यूपी एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के लिये 2,940 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी।

मुख्य बिंदु:

- नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पहले भूमि अधिग्रहण के लिये 3,000 करोड़ रुपए दिये गए थे।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में औद्योगिक विस्तार के लिये 8,000 करोड़ रुपए अलग रखे गए थे। शेष 5,000 करोड़ रुपए में से, 1,000 करोड़ रुपए UPEIDA के लिये, 1,500 करोड़ रुपए YEIDA के लिये और 440 करोड़ रुपए UPSIDA के लिये स्वीकृत किये गए हैं।
- सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के विस्तार के लिये कुल 7,042.67 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
- राज्य सरकार निवेश आकर्षित करने और उत्तर प्रदेश को देश में अग्रणी निवेश स्थल बनाने के लिये प्रतिबद्ध है।

नोट :

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA)

- यह उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 के तहत दिल्ली से सटे उनके संबंधित अधिसूचित क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास के लिये बनाया गया है, जो यदि योजनाबद्ध नहीं होते, तो अनधिकृत शहरी विकास की संभावना होती।

यूपी एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA)

- यह राज्य में एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को विकसित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित एक प्राधिकरण है।
- UPEIDA का मुख्यालय लखनऊ के गोमती नगर में पर्यटन भवन में स्थित है।

अभ्यास-अयुत्थाया और इंडो-थाई कॉर्पेट

चर्चा में क्यों ?

भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना (Royal Thai Navy - RTN) ने 'अभ्यास-अयुत्थाया (Ex-Ayutthaya)' नामक पहला द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया और द्विपक्षीय अभ्यास के साथ भारत-थाईलैंड समन्वित गश्ती दल (Indo-Thai CORPAT) का 36वाँ संस्करण भी आयोजित किया गया।

मुख्य बिंदु:

- 'अभ्यास-अयुत्थाया' का अनुवाद 'अजेय वन' या 'अपराजेय' है
- यह दो सबसे पुराने शहरों, भारत में अयोध्या व थाईलैंड में अयुत्या, ऐतिहासिक विरासतों, समृद्ध सांस्कृतिक संबंधों एवं कई सदियों तक साझा ऐतिहासिक कथाओं के महत्त्व का प्रतीक है।
- यह भारत का एक प्राचीन शहर है और भगवान श्री राम का जन्मस्थान है।
- यह महान महाकाव्य रामायण की पृष्ठभूमि है। यह प्राचीन कोसल साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी।

अयोध्या राम मंदिर

चर्चा में क्यों ?

राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा या अभिषेक समारोह सरयू तटबंध पर विष्णु पूजा और गौ दान के साथ शुरू होगा।

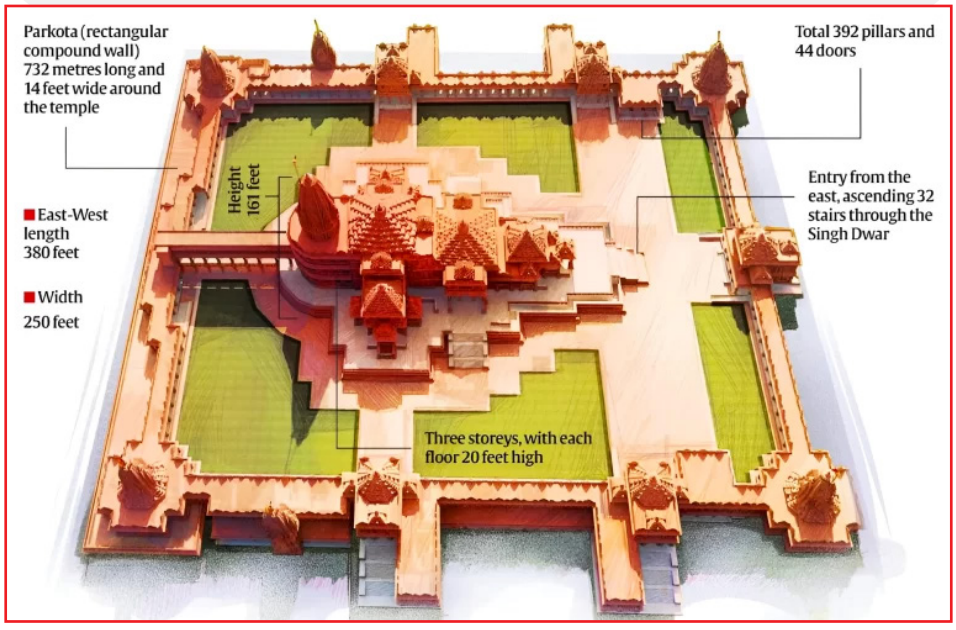

नोट :

मुख्य बिंदु:

- अयोध्या राम मंदिर का लेआउट:
  - मंदिर 20-20 फुट ऊँची तीन मंज़िलों पर बना है, जिनमें कुल 392 खंभे और 44 दरवाज़े हैं।
  - निर्माण में मकराना संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर एवं रंगीन संगमरमर का उपयोग किया गया है।
  - मंदिर की नींव रोलर-कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 मीटर मोटी परत से बनी है और ज़मीन की नमी से बचाने के लिये 21 फुट ऊँचा ग्रेनाइट प्लिंथ लगाया गया है।
  - निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है।
- मंदिर की स्थापत्य शैली, गर्भगृह , मंडप (हॉल) और मंदिरों के साथ नागर शैली है।
- परिसर का प्रत्येक कोने में सूर्य, भगवती, गणेश, शिव की मूर्ति स्थापित होगी। उत्तरी और दक्षिणी भुजाओं पर क्रमश: अन्नपूर्णा तथा हनुमान के मंदिर बनाए जाएंगे।
- महर्षि वाल्मिकी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, शबरी आदि के मंदिर भी प्रस्तावित हैं।

मंदिर वास्तुकला की नागर शैली

- इसे पहली बार उत्तर भारत में 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान विकसित किया गया था, यह शैली उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत (बंगाल क्षेत्र को छोड़कर) में लोकप्रिय है, खासकर मालवा, राजपुताना एवं कलिंग के आसपास के क्षेत्रों में।
- यह एक साधारण पत्थर के मंच पर बनाया गया है जिसमें मंदिर तक जाने के लिये सीढ़ियाँ हैं।
- इसकी विशेषताओं में शामिल हैं:
  - शिखर: गर्भगृह हमेशा उच्चतम शिखर के ठीक नीचे स्थित होता है। शिखर पर एक कलश (अमलका) भी स्थापित है।
    - शिखर के प्रकार: रेखा-प्रसाद या लैटिना (ओडिशा का श्रीजगन्नाथ मंदिर), शेखरी (खजुराहो कंदारिया महादेव मंदिर), वलभी (तेली का मंदिर), फमसाना (कोणार्क मंदिर का जगमोहन)।
- चारदीवारी या प्रवेश द्वार का अभाव।
- वे उड़ीसा शैली, चंदेल शैली और सोलंकी शैली हैं।

उत्तर प्रदेश को अपनी आतिथ्य संस्कृति से परिचित कराने का अवसर

चर्चा में क्यों ?

22 जनवरी को हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बहुप्रतीक्षित समारोह उत्तर प्रदेश को अपनी आतिथ्य संस्कृति से परिचित कराने का एक अवसर है।

मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिये थे :
  - रामलला की बालरूपी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का यह बहुप्रतीक्षित समारोह उत्तर प्रदेश को अपनी आतिथ्य संस्कृति से परिचित कराने का एक अवसर है।
  - श्री अयोध्या धाम को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त करने का प्रयास किया जाना चाहिये।
  - प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 'नव्य-दिव्य-भव्य' मंदिर पर पुष्प वर्षा का कार्यक्रम है।
  - रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम में देश-विदेश से मेहमान आ रहे हैं।
  - इसमें भारत के सभी प्रांतों से संत-महात्माओं, धर्मगुरुओं एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी।
  - इस अवसर पर भाग लेने हेतु आने वाले महानुभावों की सुरक्षा एवं सम्मान के पुख्ता इंतज़ाम किये गए। हर वीवीआईपी के साथ एक लाइज़निंग ऑफिसर तैनात किया गया।
  - इसमें ऐसे लोगों को तैनात किया गया जो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ और अयोध्या जी के पौराणिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक महत्त्व से परिचित थे।

नोट :

- अयोध्या जी को विभिन्न जनपदों से जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई।
- आगंतुकों के परिवहन के लिये इलेक्ट्रिक बसों की पर्याप्त उपलब्धता थी।

राम मंदिर प्रतिष्ठा: राज्यों ने अवकाश घोषित किया

चर्चा में क्यों ?

22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में, कई राज्यों ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की या सरकारी कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी दी।

मुख्य बिंदु:

- केंद्र सरकार के सभी कार्यालय दोपहर 2.30 बजे तक बंद रहे, कई राज्यों ने भी 22 जनवरी को 'शुष्क दिवस' घोषित किया।
- पूरे देश में केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियाँ, वित्तीय संस्थान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) आधे दिन के लिये बंद रहे।
- दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ-साथ जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान और उसके स्कूल भी दोपहर 2.30 बजे तक आधे दिन के लिये बंद रहे।
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में भी 22 जनवरी को व्यापारिक अवकाश रहा।

अयोध्या राम मंदिर

- यह 3 मंज़िला मंदिर, पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है।
- निर्माण में मकराना संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर तथा रंगीन संगमरमर का उपयोग किया गया है।
- निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है।
- मुख्य गर्भ गृह में राम लला की मूर्तियाँ हैं, साथ ही रंग मंडप और नृत्य मंडप सहित कई मंडप हैं।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NSE) भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाज़ार है।
- वर्ष 1992 में निगमित, NSE एक परिष्कृत, इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार के रूप में विकसित हुआ है जो इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से विश्व में चौथे स्थान पर है।
- NSE भारत में आधुनिक, पूर्णत: स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रदान करने वाला पहला एक्सचेंज था।
  - NSE भारत में सबसे बड़ा निजी वाइड-एरिया नेटवर्क है।
- NIFTY 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) का प्रमुख सूचकांक है।

रैपिड रेल कॉरिडोर के लिये 16,000 करोड़ रुपए की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए की रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंज़ूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में कई हवाई अड्डों को निर्बाध रूप से जोड़ना है।

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) इस कॉरिडोर के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसे मार्च 2024 तक अंतिम रूप दिये जाने की उम्मीद है।

मुख्य बिंदु:

- एक बार शुरू होने के बाद, चार वर्ष के अनुमानित समापन समय के साथ यह परियोजना दो प्रमुख हवाई अड्डों और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेगी।

नोट :

- इससे आगामी नोएडा हवाई अड्डे को दिल्ली हवाई अड्डे से यात्री यातायात के अतिप्रवाह को पकड़ने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
- प्रस्तावित नोएडा हवाईअड्डा लिंक गाज़ियाबाद स्टेशन से शुरू होगा, जो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट के लिये एक इंटरचेंज बिंदु के रूप में कार्य करेगा।
- यात्रियों के पास दिल्ली-मेरठ रेल के शुरुआती स्टेशन सराय काले खाँ के माध्यम से प्रगतिरत दिल्ली-अलवर रैपिड रेल से जुड़ने का विकल्प भी होगा।
- दिल्ली-अलवर रेल, वर्ष 2025 के मध्य तक समाप्त होने की उम्मीद है, इसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और एयरोसिटी का स्टेशन शामिल होगा।
- नोएडा हवाई अड्डे के अधिकारी दिल्ली और गुड़गाँव के साथ एक व्यापक मल्टी-मॉडल परिवहन कनेक्टिविटी नेटवर्क स्थापित करने के लिये हाई-स्पीड बस कॉरिडोर सहित अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों को विकसित करने पर भी कार्य कर रहे हैं।

अयोध्या में BHISHM क्यूब

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भीष्म (भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री- BHISHM) क्यूब, अयोध्या में स्थित एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है जो प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का हिस्सा है।

- यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान एक चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में एक जीवनरक्षक के रूप में उभरकर आया।

मुख्य बिंदु:

- आरोग्य मैत्री परियोजना में भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों के प्रभाव का सामना करने वाले किसी भी विकासशील देश को महत्त्वपूर्ण चिकित्सा संसाधनों की आपूर्ति करना शामिल है।
- BHISHM क्यूब को त्वरित प्रतिक्रिया और समग्र देखभाल पर बल देते हुए 200 हताहतों तक के उपचार के लिये तैयार किया गया है।
- यह एड क्यूब (Aid Cube) आपात स्थितियों के दौरान आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता वृद्धि करने हेतु निर्मित कई नवोन्मेषी उपकरणों से युक्त है।
- यह क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के प्रभावी समन्वय, वास्तविक समय की निगरानी और कुशल प्रबंधन को सुगम बनाने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI) तथा डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत करता है।
- BHISHM क्यूब की सफलता आपात स्थिति के दौरान तत्काल और प्रभावी चिकित्सा सहायता प्रदान करने में मोबाइल अस्पताल इकाइयों के महत्त्व को रेखांकित करती है।

कानपुर में GSVM मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल (GSVM) मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन किया।

- उन्होंने कानपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग (AIISH) सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला भी रखी।

मुख्य बिंदु:

- सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 12 विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है और इसका उद्देश्य लोगों के समय तथा संसाधनों की बचत करते हुए इन सेवाओं को स्थानीय स्तर पर प्रदान करना है।
  - ब्लॉक का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के तहत किया गया है।

नोट :

- कानपुर में AIISH केंद्र उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक केंद्र है। यह न केवल डॉक्टरों को प्रशिक्षित करता है बल्कि लोगों की देखभाल भी करता है।
  - केंद्र भाषण-भाषा विकृति विज्ञान, ऑडियोलॉजी, संचार विकार की रोकथाम, टेली-मूल्यांकन और पुनर्वास सहित चार विशिष्ट प्रभागों को संभालता है।
- भारत में एम्स की संख्या 6 से बढ़कर 23 हो गई है, मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या लगभग दोगुनी होकर 710 तक पहुँच गई है, जन औषधि केंद्र 10,000 से अधिक हो गए हैं और आयुष्मान भारत योजना के तहत 160 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किये गए हैं।
  - उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहाँ दो एम्स हैं। इसके अलावा, पिछले 10 वर्षों में राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई है।
- सरकार ने सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण देखभाल तथा उपचार का दायरा बढ़ाया है।
  - 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभ पाने के हकदार हैं और 50 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) आईडी कार्ड बनाए गए हैं।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)

- यह योजना मार्च 2006 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य सामान्य रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को ठीक करना और विशेष रूप से कम सेवा वाले राज्यों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाना है।
- इसके दो घटक हैं:
  - एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना।
  - सरकारी मेडिकल कॉलेज संस्थानों का उन्नयन।

उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2024

चर्चा में क्यों ?

24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना 75वाँ स्थापना दिवस मनाया। इस दिन को हिंदी में उत्तर प्रदेश दिवस या यूपी दिवस के नाम से जाना जाता है।

मुख्य बिंदु:

- वैदिक काल में राज्य को ब्रह्मऋषि देश या मध्य देश कहा जाता था।
  - मुगल काल के दौरान, इसका क्षेत्र राज्यपालों के अधीन विभाजित था।
- 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया।
  - वर्ष 1947 से 1950 तक भारत ब्रिटिश सिद्धांतों का पालन करता रहा, जिसके कारण इस दौरान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत रहे। परिणामस्वरूप उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ।
- 'उत्तर प्रदेश दिवस' मनाने की पहल तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने की थी और यह कार्यक्रम वर्ष 2018 से प्रत्येक वर्ष तीन दिनों तक मनाया जाता है।
- 24 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक लखनऊ, दिल्ली और नोएडा में कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
  - एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) के तहत सभी ज़िलों में शिल्पोत्सव के साथ-साथ कई उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा, जैसे लखनऊ में अवध शिल्पग्राम, नोएडा हाट सेक्टर-32 और दिल्ली के कनॉट प्लेस में खड़क सिंह मार्ग।
    - शिल्पोत्सव समाज के कमज़ोर वर्गों से संबंधित देश भर के कारीगरों का वार्षिक मेला है।
  - एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के शिल्पकारों के उत्पाद एवं राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये।

एक भारत श्रेष्ठ भारत

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिये लॉन्च किया गया था ताकि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में आपसी समझ और बंधन को बढ़ाया जा सके, जिससे भारत की एकता और अखंडता मज़बूत होगी।

नोट :

- राज्य भाषा सीखने, संस्कृति, परंपराओं एवं संगीत, पर्यटन एवं व्यंजनों, खेल एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने आदि के क्षेत्रों में एक निरंतर और संरचित सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा देने के लिये गतिविधियों का संचालन करते हैं।

खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, भारत सरकार द्वारा हर ज़िले में स्थापित किये जा रहे 'खेलो इंडिया सेंटर' की तर्ज पर राज्य के हर ब्लॉक में 'खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर' की स्थापना की जाएगी।

मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय खेल मंत्री ने लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 19वें एशियाई खेल-2022, चौथे पैरा एशियाई खेल-2022 और 37वें राष्ट्रीय खेल-2023 में पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया।
  - प्रदेश के 189 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 62 करोड़ रूपए की पुरस्कार राशि वितरित की गयी।
  - इसके साथ ही सात पदक विजेता खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक, ज़िला युवा कल्याण अधिकारी एवं यात्री/माल कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति पत्र भी दिये गये।
- जो खिलाड़ी खेल के बाद अपना समय दे सकेंगे, उन्हें निश्चित मानदेय पर 'खेलो यूपी सेंटर' में कोच नियुक्त किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश देश की 16% आबादी का निवास स्थान है और यूपी के खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में 25% पदक जीते हैं।

खेलो इंडिया कार्यक्रम

- खेलो इंडिया योजना का उद्देश्य पूरे देश में खेलों को प्रोत्साहित करना तथा इस प्रकार अपने क्रॉस-कटिंग प्रभाव नामत:- बच्चों और युवाओं का समग्र विकास, सामुदायिक विकास, सामाजिक एकीकरण, लैंगिक समानता, स्वस्थ जीवन शैली, राष्ट्रीय गौरव और खेलों के विकास से जुड़े आर्थिक अवसरों के माध्यम खेल क्षमताओं का दोहन करने की अनुमति देती है।
- इस योजना के तहत, विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता वाले खेल विषयों में पहचान प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्षों तक के लिये प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :